सतत विकास के लक्ष्य के साथ वित्त मंत्री ने विधान सभा में **पहली बार** पेश की प्रदेश की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट

नौ साल में दोगुणी हो गई प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय

- डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा, पर्यावरण संतुलन और कौशल विकास को प्राथमिकता
- राज्य की अर्थव्यवस्था हो जाएगी 36 लाख करोड़ रुपये की, विपक्ष ने की चर्चा की मांग

30.25 लाख करोड़ रुपये हो गया एसजीडीपी का आकार

50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव सरकार को मिले

9.1 प्रतिशत हिस्सा है उत्तर प्रदेश का देश की जीडीपी में

कार्यवाही के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना • प्रेट्र

अभिभाषण देतीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, साथ में विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना व विप के सभापति कुंवर मानवेंद्र • जागरण

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने केंद्र सरकार की तरह सोमवार को बजट सत्र के पहले दिन राज्य की आर्थिक समीक्षा को विधान सभा में प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के आधार पर वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,26,304 रुपये हो गई है। वर्ष 2016-17 में यह 61,142 रुपये थी। आजादी के समय प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर थी। यह गिरते-गिरते यह वर्ष 2014-15 में 50.2 प्रतिशत पर आ गई। वर्ष 2024-25 में बड़े बदलाव के साथ प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 53.5 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आर्थिक समीक्षा-2025-26 की रिपोर्ट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत नींव पर खड़ी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्य सरकार ने आर्थिक समीक्षा को विधान सभा में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि समीक्षा में आकड़ों के साथ ही राज्य के विकास, जनता की आकांक्षाओं और भविष्य की संभावनाएं शामिल की गई हैं। विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश-2047 विजन डाक्यूमेंट आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक समावेश और पारदर्शिता की दूरदर्शी परिकल्पना है। सरकार का फोकस निवेश, रोजगार और सतत विकास पर रहेगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा और पर्यावरणीय संतुलन को प्राथमिकता देते हुए युवाओं को कौशल विकास और स्टार्टअप योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में संतुलित विकास ने राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सामाजिक योजनाओं ने आमजन को राहत दी है। अवसंरचना परियोजनाओं ने भविष्य की दिशा तय की है। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2016-17 में राज्य की अर्थव्यवस्था 13.30 लाख करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2024-25 में दोगुणे से अधिक होकर 30.25 लाख करोड़ रुपये हो गई है। चालू वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था 36 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पारदर्शी नीतियों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव राज्य को मिल चुके हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रदेश का योगदान वर्ष 2016-17 में 8.6 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 9.1 प्रतिशत हो चुका है।

संबंधित खबर » 11

संवाद से समस्या के समाधान में विश्वास करती है सरकार : योगी

लखनऊ : बजट सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा कि हमारी सरकार 10वां बजट पेश करेगी। किसी सदस्य को कोई मुद्दा उठाना है तो सदन की कार्यवाही बाधित करने के बजाय संवाद करे, क्योंकि हमारी सरकार संवाद से समस्या के समाधान में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र प्रदेश के विकास की गति को और तेज करने में भूमिका का निर्वहन करेगा। हम चर्चा के लिए तैयार रहते हैं। देखें » 11

सुशासन से समृद्धि तक, राज्यपाल ने अभिभाषण में गिनाईं उपलब्धियां

लखनऊ : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की नौ वर्षों की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि प्रदेश अब संभावनाओं का नहीं, बल्कि उपलब्धियों का प्रदेश बन चुका है। राज्यपाल ने विपक्ष के शोर-शराबे व नारेबाजी के बीच 30 मिनट में अभिभाषण पूरा पढ़ा। 55 पेज के भाषण में राज्यपाल ने सुशासन, सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, मजबूत और समावेशी आर्थिक विकास की उपलब्धियों को सामने रखा। देखें » 11